मोती उत्पादन को करें प्रोत्साहित

मछुआ कल्याण व मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने दिए निर्देश

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 22 जून. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि एकीकृत मत्स्योघोग नीतिः 2026 के कारण प्रदेश में मछली पालन सेक्टर में 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आ रहा है.

प्रदेश में मोती उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाये, इसके लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन कर उनका क्रियान्वयन प्रदेश में सुनिश्चित किया जायें. प्रदेश को मछली उत्पादन में आत्म निर्भर बनाना जरूरी है. अगले ढाई साल में हमें मछली बीज अन्य स्थानों से नहीं खरीदना पड़े, इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर विभाग कार्य करे. हर जिले में एक हेचरी आवश्यक रूप से विकसित की जाये. जिलों में मछली बीज आसानी से मिलने से प्रदेश में मछली उत्पादन में और बढ़ोत्तरी होगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश मंत्रालय में मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे मछली उत्पादन को देखते हुए कोल्ड चेन तथा अन्य आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाये. ब्रांडिंग और निर्यात के लिए आवश्यक नेटवर्किंग को भी प्रोत्साहित किया जाये.

> मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नदियों के पुनर्जीवन, जलीय जीवों के संरक्षण के लिए सभी संबंधित विभाग परस्पर समन्वय से कार्य करें. जलीय ईको सिस्टम को विकसित करने और जल सम्पदा पर आधारित पर्यटन गतिविधियों को विस्तार देने के लिए भी कार्य योजना बनाई जाये. मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अन्तर्देशीय जल क्षेत्र में मप्र देश में दूसरे स्थान पर है.

'गोल्डन ऑवर हीरो' अभियान से सड़क हादसों में 33% कमी

विशेष संवाददाता

भोपाल, 22 जून. नरसिंहपुर पुलिस द्वारा शुरू की गई अभिनव सड़क सुरक्षा पहल 'गोल्डन ऑवर हीरो' ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं, मौतों और गंभीर रूप से घायल होने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज कराई है.

वर्ष 2026 के जनवरी से मई के बीच इस अभियान के प्रभाव से सड़क दुर्घटनाओं में 33 प्रतिशत, मृत्यु दर में 23 प्रतिशत तथा गंभीर रूप से घायल होने वाले लोगों की संख्या में 52 प्रतिशत की कमी आई है. सड़क दुर्घटना के बाद का पहला घंटा, जिसे 'गोल्डन ऑवर' कहा जाता है, पीड़ित के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए नरसिंहपुर पुलिस ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे स्थित ढाबा संचालकों, पेट्रोल पंप कर्मचारियों तथा स्थानीय ग्रामीणों को चिन्हित कर उन्हें सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया. आपातकालीन सहायता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विशेष व्हाट्सएप समूह बनाए गए, सरकारी राहत योजनाओं की जानकारी दी गई तथा फर्स्ट एड बॉक्स वितरित किए गए. इन प्रयासों से दुर्घटना पीड़ितों तक त्वरित सहायता पहुंचाने में सफलता मिली.

प्री-मानसून में झमाझम बारिश होने से ठंडक

धार, उज्जैन, भोपाल सहित जिलों में हुई बरसात

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 22 जून. मप्र में प्री-मानसून के दौरान झमाझम बारिश की शूरूआत हो गई है. सोमवार को प्रदेश के धार, उज्जैन, बड़वानी, रायसेन, भोपाल सहित जिलों में बारिश होने से ठंडक बनी रही.

इन जिलों में करीब आधे घंटे तक बारिश होती रही. देर शाम तक रिमझिम बारिश का दौर भी इस बीच जारी रहा है. मौसम विभाग ने प्रदेश में 25 जून तक मानसून के दस्तक देने की संभावना जताई है. मानसून के आने से पहले ही प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी हो चुका है. मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी दिनों में भी जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. राजगढ़, शाजापुर, आगर, दमोह, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनुपपुर, जबलपुर सहित जिलों में बारिश की संभावना जताई है. जिलों में बिजली के साथ मध्यम गरज (हवा की गति 60 किमी प्रति घंटे) के साथ-साथ रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी में बिजली (40 किमी प्रति घंटे तक की हवा) के साथ हल्की आंधी चलने की संभावना है. इंदौर, देवास, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, चित्रकूट, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली सहित जिलों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है.

राजधानी में भी झमाझम बरसात

भोपाल. राजधानी सहित प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में सोमवार को झमाझम बारिश हुई. भोपाल के कोलार इलाके में दोपहर के करीब 12 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ. आधे घंटे की बारिश होने से कई निचले स्थानों पर बारिश का पानी भी जमा हो गया. शहरभर में इस बीच बूंदा बांदी होती रही. आसमान में लगातार बादलों के घिरे होने से मौसम पूर तरह से ठंड़ा रहा. हल्की ठंड़ी हवाओं के चलने से लोगों को गर्मी से निजात मिली.

यूसीसी पर भाकपा की सर्वदलीय बैठक की मांग

निज संवाददाता

भोपाल, 22 जून.मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने इस प्रस्ताव को अनावश्यक बताते हुए राज्य सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है.

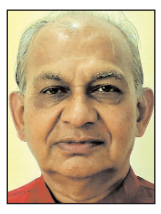

भाकपा के राज्य सचिव कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को भेजे पत्र में कहा है कि समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव कई विसंगतियों और अंतर्विरोधों से भरा है.उनका कहना है कि आम जनता को इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों के हित में समान आर्थिक संहिता अधिक जरूरी है, जिससे आर्थिक समानता और खुशहाली सुनिश्चित हो सके. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा इस विषय पर ऑनलाइन राय मांगी जा रही है,जबकि प्रदेश की बड़ी आबादी अब भी ऑनलाइन सुविधाओं से वंचित है. ऐसे में बिना सभी वर्गों की राय लिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला लेना उचित नहीं होगा.

मां की याद में हरियाली का संकल्प, तेहरवीं पर 5 हजार पौधे सौंपे

धार. जिले के अमझेरा गांव में एक परिवार ने शोक को सेवा में बदलकर मिसाल पेश की.मां के निधन के बाद जहां लोग रस्में निभाते हैं, वहीं शर्मा परिवार ने पर्यावरण बचाने का रास्ता चुना. तेहरवीं के मौके पर परिवार ने करीब एक लाख रुपए कीमत के पांच हजार पौधे जिला प्रशासन को सौंप दिए. परिवार के अश्विन शर्मा, अरुण शर्मा और अविनाश शर्मा ने बताया कि वे प्रधानमंत्री की 'एक पेड़ मां के नाम' पहल से प्रेरित हुए. उन्होंने कहा कि अब उनकी मां की याद इन पेड़ों के रूप में जिंदा रहेगी. गांव में भी इस पहल की खूब चर्चा हो रही है और लोग इसे अनोखी श्रद्धांजलि मान रहे हैं.

यूसीसी पर भाजपा के महत्वपूर्ण सुझाव

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 22 जून. प्रदेश भाजपा ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की समिति को सौंपे हैं.

पार्टी के प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी और एक अन्य पदाधिकारी एस. एस. उप्पल ने सुझाव पत्र सौंपा. पत्र में विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर कड़े कानून बनाने का अनुरोध किया गया है. सुझाव पत्र में विवाह में पूर्ण पारदर्शिता रखने पर विशेष जोर दिया गया है. पार्टी का सुझाव है कि शादी से पहले दोनों पक्षों द्वारा अपनी पहचान, नागरिकता, वैवाहिक स्थिति और पूर्व विवाह या तलाक से जुड़े तथ्यों का प्रकटीकरण अनिवार्य किया जाए. वहीं जानबूझकर तथ्य छिपाने या गलत जानकारी देकर विवाह करने को दंडनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए.

> **पार्टी द्वारा सौंपे गए सुझाव: 1.** पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम कानूनी आयु का सख्ती से पालन कराना
> **2.** पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति में बेटे और बेटी को समान अधिकार, साथी की मृत्यु के बाद जीवित जीवनसाथी के अधिकार सुरक्षित हों. सभी नागरिकों को बच्चा गोद लेने का कानूनी अधिकार और उन्हें समान रूप से संपति में अधिकार दिलाना. **3.** बच्चों के प्राकृतिक संरक्षक के रूप में माता और पिता दोनों को समान कानूनी दर्जा दिया जाए. **4.** विवाह, तलाक या भरण-पोषण से जुड़े पारिवारिक विवादों का निपटारा अधिकतम 6 महीने के भीतर हो.

यूसीसी : असली मुद्दों से ध्यान भटकाया

मूलभूत मुद्दों पर जवाब देने के बजाय सरकार यूसीसी की बहस कर रही

विशेष संवाददाता

भोपाल, 22 जून. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने को लेकर चल रही चर्चा भारतीय जनता पार्टी सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जनता का ध्यान प्रदेश के ज्वलंत सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से हटाना है।

एक बयान में पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश की जनता इस समय बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और आदिवासी समुदाय के कल्याण से जुड़े गंभीर प्रश्नों का सामना कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मूलभूत मुद्दों पर जवाब देने के बजाय राज्य सरकार यूसीसी की बहस को आगे बढ़ाकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आदिवासी समुदाय के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों और गारंटियों के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार से जुड़े वादों पर अब तक क्या प्रगति हुई है.

> पटवारी ने आदिवासी महिलाओं के लापता होने की घटनाओं तथा आदिवासी समाज के लोगों के खिलाफ अत्याचार और शोषण के आरोपों पर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि प्रभावित महिलाओं को न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा ऐसे मामलों में जवाबदेही क्यों तय नहीं हो पा रही है. यदि यूसीसी को आवश्यक माना जा रहा है तो सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि इसके तहत आदिवासी परंपराओं, रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान और संवैधानिक संरक्षणों की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी.

इमरजेंसी वार्ड हटाने पर गैस पीड़ितों का विरोध

निज संवाददाता

भोपाल, 22 जून. गैस पीड़ितों के चार संगठनों ने कमला नेहरू गैस राहत सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड हटाकर पीईटी-सीटी केंद्र बनाने की योजना का कड़ा विरोध किया है.संगठनों ने इसे अवैध, असुरक्षित और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ बताया है.

भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा की नसरीन खान ने कहा कि निविदा शर्तों के अनुसार पीईटी-सीटी केंद्र गांधी मेडिकल कॉलेज में बनाया जाना है, लेकिन इसे अस्पताल में स्थानांतरित किया जा रहा है.निविदा पाने वाली संस्था श्री अरविंदो आयुर्विज्ञान संस्थान ने भी लिखित में बताया है कि इमरजेंसी वार्ड को रेडियोलॉजी विभाग में ले जाना तकनीकी और संचालन के लिहाज से संभव नहीं है और इसमें 10 से 12 महीने लगेंगे. भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की रशीदा बी ने कहा कि इमरजेंसी सेवाओं को उच्च विकिरण वाले केंद्र के साथ रखना मरीजों के लिए खतरा है और यह परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नियमों का उल्लंघन हो सकता है.उन्होंने बताया कि अब तक कोई स्वतंत्र विकिरण सुरक्षा जांच नहीं हुई है.

रेलवे ने किया विशेष रेलगाड़ी का संचालन

कानपुर सेंट्रल-तिरुच्चिरापल्ली के बीच गाड़ी का संचालन

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 22 जून. रेलवे प्रशासन द्वारा कानपुर सेंट्रल एवं तिरुच्चिरापल्ली के मध्य विशेष रेलगाड़ी का संचालन किया जा रहा है. यह विशेष रेलसेवा पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल के बीना, भोपाल एवं इटारसी स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे मंडल के यात्रियों को दक्षिण भारत की यात्रा हेतु अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध होगी.

गाड़ी संख्या 01927 कानपुर सेंट्रल-तिरुच्चिरापल्ली विशेष रेलगाड़ी प्रत्येक बुधवार 24 जून 2026 को कानपुर सेंट्रल से प्रातः 08:10 बजे प्रस्थान कर मार्ग में पुखरायां, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ललितपुर होते हुए बीना स्टेशन पर 15:40 बजे आगमन एवं 15:45 बजे प्रस्थान, भोपाल स्टेशन पर 17:20 बजे आगमन एवं 17:25 बजे प्रस्थान तथा इटारसी स्टेशन पर 19:25 बजे आगमन एवं 19:30 बजे प्रस्थान करेगी.

भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तित

भोपाल. रेलवे ने नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते दो ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी परिवर्तन किया गया है. भोपाल से चलने वाली दो ट्रेनें अब परिवर्तित मार्ग से संचालित की जाएंगी. रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर सूचना जारी की गई है. रेलवे की सूचना के मुताबिक पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल में छिपोधर-बरवाडीह-मंगरा रेलखंड पर तृतीय अप लाइन के कमीशनिंग कार्य के संबंध में किए जा रहे नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी परिवर्तन किया गया है.

पटवारियों के 411 पद मंजूर

नवभारत न्यूज

सीधी 22 जून. जिले में पटवारियों की कमी के चलते राजस्व कार्य काफी प्रभावित हो रहे हैं. स्थिति यह है कि सीधी जिले में पटवारियों को 411 पद स्वीकृत हैं. इसके विरुद्ध महज 267 पटवारी पदस्थ हैं.

पटवारियों की कमी के चलते एक पटवारी को दो-तीन हल्कों का प्रभार सौंपा गया है. ऐसी स्थिति में प्रभार वाले पटवारी हल्कों का कार्य सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है. पटवारियों की कमी के चलते किसानों के साथ ही आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. समय के साथ सीधी जिले में पटवारी हल्कों की संख्या में बढ़ोत्तरी भी की गई है. जिले में 8 तहसीलें हैं जहां गांवों की संख्या करीब 1072 है. इतने बड़े क्षेत्र के मुकाबले केवल 267 पटवारी ही पदस्थ हैं. जबकि 144 पटवारियों के पद रिक्त पड़े हैं. कुछ पटवारी रिश्वतखोरी के चलते लोकायुक्त के शिकंजे में भी फंस चुके हैं. वहीं कुछ को कार्यालय में अटैच किया गया है. पिछले कई माह से पटवारियों की कमी की समस्या बनी हुई है. विडम्बना यह है कि जिला स्तर से उक्त समस्या की जानकारी राज्य सरकार को भेजी जाती है फिर भी शासन स्तर से पटवारियों की कमी को पूरा करने के लिए वैकेंसी निकालने की जरूरत नहीं समझी जा रही है. शासन द्वारा आवश्यक संख्या में पटवारियों की भर्ती नहीं की जाती.

स्कूल वाहन पलटा सात बच्चे घायल

छिंदवाड़ा. कोतवाली क्षेत्र में सोमवार को एक स्कूल वेन अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में सात बच्चे घायल हो गए. हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है. दो बच्चों को जिला अस्पताल लाया गया. वही पांच बच्चे को निजी अस्पताल ले जाया गया. एक बच्चे को छोड़कर अन्य बच्चों को प्राथमिक इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया. एक निजी स्कूल के बच्चे छुट्टी होने के बाद स्कूल वाहन से घर लौट रहे थे. इस दौरान वाहन चालक ने कुछ बच्चों को घर छोड़ दिया था. तकरीबन सात बच्चों को लेकर वह घर छोडने जा रहा था. इस दौरान वाहन अनियंत्रित हो गया और ओवर ब्रिज की बाउंड्री बॉल में जा घुसा.

मंदिर ट्रस्टों की वित्तीय जांच की मांग

कांग्रेस ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

विशेष संवाददाता

भोपाल, 22 जून. मध्यप्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने देश के प्रमुख मंदिर ट्रस्टों और धार्मिक परियोजनाओं की वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए उनकी स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है.

कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की

कांग्रेस नेता ने कहा कि श्रद्धालुओं को यह जानने का पूरा अधिकार है कि मंदिरों में प्राप्त दान और संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है. उन्होंने देशभर के प्रमुख मंदिर ट्रस्टों, धार्मिक संस्थानों और मंदिर निर्माण परियोजनाओं का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ऑडिट कराने, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने तथा अनियमितता सिद्ध होने पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की.

उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े विभिन्न मंदिर ट्रस्टों ने धर्म, आस्था और सनातन परंपराओं के नाम पर जनता की भावनाओं का राजनीतिक उपयोग किया है, जबकि कई बड़े धार्मिक प्रकल्पों से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का अब तक संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है.

मुकेश नायक ने कहा कि उज्जैन के महाकाल लोक तथा ओरछा में प्रस्तावित श्रीराम महालोक परियोजना समेत कई मंदिर विकास एवं पुनरुद्धार योजनाओं पर वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लग चुके हैं. उन्होंने दावा किया कि ओरछा परियोजना में 50 रुपये प्रति वर्गफुट कीमत वाली टाइलें कथित रूप से 350 रुपये प्रति वर्गफुट तक की दर पर खरीदी गईं, जिससे सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की आशंका पैदा होती है.

अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई

विशेष संवाददाता

भोपाल, 22 जून. मध्यप्रदेश पुलिस ने विशेष अभियान के तहत पिछले 15 दिनों में राज्यभर से 52 अवैध हथियार जब्त किए हैं.

पुलिस की कार्रवाई अवैध हथियार फैक्ट्रियों, हथियार तस्करों और आपराधिक गतिविधियों में शामिल संदिग्धों पर केंद्रित रही. भिंड में पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण इकाई का भंडाफोड़ करते हुए एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया और हथियारों के साथ अर्धनिर्मित हथियार भी बरामद किए. खरगोन पुलिस ने 12 देशी पिस्टल और सात मैगजीन जब्त कीं. दतिया, ग्वालियर, छतरपुर, रतलाम, बुरहानपुर, जबलपुर और अशोकनगर, मुरैना में भी कार्रवाई हुई.

रिपोर्ट | देश में 30.6 और मध्यप्रदेश में केवल 19.6% स्कूलों में है स्मार्ट क्लास

स्मार्ट क्लासरूम के मामले में एमपी पिछड़ा

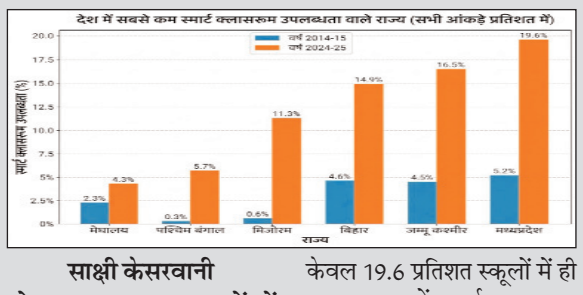

साक्षी केसरवानी

भोपाल, 22 जून. स्कूलों में पारंपरिक ब्लैक बोर्ड की जगह आधुनिकता को बढ़ावा देने स्मार्ट क्लास रूम की शुरुवात की जा चुकी है. लेकिन इस दौड़ में मध्य प्रदेश पीछे छूट गया है.

नीति आयोग द्वारा मई 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, मप्र के केवल 19.6 प्रतिशत स्कूलों में ही चालू हालत में स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा उपलब्ध है. जिसका सीधा मतलब है, कि राज्य के करीब 80 प्रतिशत स्कूलों में बच्चे आज भी आधुनिक सुविधाओं और सरकार की योजनाओं से कोसों दूर हैं. विद्यार्थियों को आधुनिकता के नाम पर स्कूलों में केवल ये शब्द ही पढ़ने को मिल रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड और पीपीटी के जरिए पढ़ाई जाने वाले एक्टिव लर्निंग की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है. हालांकि रिपोर्ट के अनुसार देशभर में साल 2014-15 में कुल 14.9 प्रतिशत स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम मौजूद थे. जो कि साल 2024-25 में बढ़कर 30.6 प्रतिशत तक ही पहुंच सका है.

> **सबसे कम स्मार्ट क्लासरूम वाले राज्य**
> रिपोर्ट के मुताबिक मप्र इस मामले में देश के सबसे निचले पायदान वाले राज्यों की कतार में खड़ा है. तो वहीं डिजिटल बुनियादी ढांचे के इस ग्राफ में मेघालय में 4.3, पश्चिम बंगाल में 5.7 और मिजोरम में 11.3 प्रतिशत स्कूलों में ही ये सुविधा उपलब्ध है. इसके बाद बिहार में 14.9 प्रतिशत, जम्मू कश्मीर में 16.5 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 19.8 प्रतिशत स्कूलों में ही स्मार्ट क्लासरूम पहुंच सके हैं. स्मार्ट क्लासरूम के मामले में देश में सबसे शानदार स्थिति चंडीगढ़ की है, जहां के 95.2 प्रतिशत स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम चालू हैं. इसके बाद लक्षद्वीप में 86.1 प्रतिशत, पंजाब में 80.1 प्रतिशत, दिल्ली में 75.7 प्रतिशत और पुडुचेरी में 72.5 प्रतिशत स्कूलों में यह व्यवस्था काम कर रही है.

पारिवारिक विवाद में युवक की हत्या

बैतूल. जिले के भैंसदेही क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. बहू को मायके से विदा कराने पहुंचे परिवार पर हमला हो गया.इसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि उसका बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल है.पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. ग्राम जूनापानी में मरामझिरी निवासी प्रवीण मरकाम अपने परिवार के साथ बड़े बेटे की पत्नी को लेने पहुंचे थे.इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई.प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद बढ़ने पर लात घूंसों से हमला किया गया. हमले में प्रवीण मरकाम के बेटे आकाश मरकाम और विशाल मरकाम गंभीर रूप से घायल हो गए.

पेज एक का शेष

पिकअप को ट्रक ने मारी टक्कर, 6 लोगों की मौत

उक्त घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया जहां उपचार के दौरान एक अन्य मजदूर की मौत हो गई. 21 घायलों का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. बाइक चालक के हुए दो टुकड़े इधर ट्रक और पिकअप की चपेट में एक बाइक चालक संतोष पिता केषवराव सवनेरे उम्र 46 साल ग्राम हथलेवा आ गया। बाइक के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में चालक के शरीर के दो टुकड़े हो गए. शव उठाने के दौरान कर्मी उसके शरीर को ढूढते नजर आए.

हादसे में इनकी हुई मौत

1.बब्बू पिता भूरु राजबैठे 35 साल
2.संतोष पिता केशराव सवनेरे 45 साल
3.सावित्री पति सुरेश बनके 31 साल
4.शिवकली पति तुमराम 45 साल
5.लीलावती पति गरीबा शीलू 45 साल निवासी ग्राम मचेरा
6.सुकरवती बाई पति रामचरन उम्र 40 साल निवासी ग्राम मछेरा

हादसे में ये हुए घायल

(1) करीना पिता सरवन ढीकू
(2) सुनीता पति दयाराम बनके
(3) गरिता पिता बबलू शीलू
(4) सकल बती पति गुड्डू सकोम
(5) शशीकला पति मंदरे वाडिवा
6 पायल पिता महेश ठीकू
7 कंचन पिता कैलाश सकोम
8 माया पिता दशरू बट्टी
9.झुमरवती पति अम्मी लाल
10 अनीता पति संजय ढीकू
11 रोशनी पिता अजय शीलू
12 निशा पिता शंकर तुमडाम
13 सलोनी पिता सोमू वाडिवा
14 गिरजा पति किशोर वाडिवा
15 किरण पिता चंदर वाडिवा
16 हसीना पिता अजय शीलू
17 बुजवती पति रामलाल बनके
18 रविना पिता झीमा वन
19 पुजा पिता महेश ढीकू
20 आयुषी पिता सुरज बनके
21 श्याम जी पिता जंगल सिंह भोसोम